भारत सरकार
संचार मंत्रालय
दूरसंचार विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 3881
उत्तर देने की तारीख 17 जुलाई, 2019

ग्रामीण क्षेत्रों में दूरसंचार संपर्क

3881. श्री कोमती रेड्डी वेंकट रेड्डीः श्री वाई.एस. अविनाश रेड्डीः

क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार का विचार संपूर्ण देश के ग्रामीण और दूर-दराज के क्षेत्रों में दूरसंचार संपर्क में तेजी लाने के लिए कोई कदम उठाने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध् में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं;

(ग) क्या आंध्र प्रदेश राज्य में सरकार द्वारा ऐसा कोई क्षेत्र चिन्हित किया गया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) क्या उक्त प्रयोजनार्थ सरकार द्वारा कोई रूप रेखा बनाई गई है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर
संचार, विधि और न्याय तथा इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री
(श्री रविशंकर प्रसाद)

(क) और (ख): देश के ग्रामीण और दूरस्थ क्षेत्रों में दूरसंचार कनेक्टिविटी को गति देने के लिए सरकार द्वारा निम्नलिखित परियाजनाओं का कार्यान्वयन किया जा रहा है:

(i) वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित क्षेत्र चरण-।। परियोजना के अंतर्गत सरकार ने मोबाइल कनेक्टिविटी प्रदान करने के लिए मोबाइल टावर संस्थापित करने की संस्वीकृति प्रदान की है।

(ii) पूर्वोत्तर क्षेत्र में कवर न किए गए गांवों, राष्ट्रीय राजमार्गों के साथ-साथ मोबाइल कवरेज प्रदान करने और ट्रांसमिशन नेटवर्क को मजबूत बनाने के लिए मोबाइल कनेक्टिविटी हेतु व्यापक दूरसंचार विकास योजना।

(iii) अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को कनेक्टिविटी प्रदान करने के लिए चेन्नई और अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह के बीच सबमरीन ओएफसी केबल बिछाना।

(iv) अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के लिए 4 जीबीपीएस तक सेटेलाइट बैंडविड्थ संवर्धन।

(v) अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में कवर न किए गए गांवों और राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 223 को कवर करने के लिए मोबाइल कनेक्टिविटी।

(vi) कवर न किए सीमावर्ती क्षेत्रों, लद्दाख और कारगिल क्षेत्र तथा अन्य प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रों के 361 गांवों में मोबाइल कनेक्टिविटी प्रदान करने के लिए स्कीम।

(vii) लक्षद्वीप समूह के लिए सेटेलाइट बैंडविड्थ 318 एमबीपीएस से बढ़ाकर 1.17 जीबीपीएस करना।

(viii) भारतनेट परियोजना के अंतर्गत देश की लगभग सभी 2.50 लाख ग्राम पंचायतों को ब्राडबैंड कनेक्टिविटी प्रदान करना।

(ग) और (घ): वर्ष 2018 में दूरसंचार सेवा प्रदाताओं से एकत्र किए गए आंकड़ों के अनुसार यह अनुमान लगाया गया था कि 2011 की जनगणना के अनुसार आंध्र प्रदेश के 16,158 आबाद गांवों में से 2745 गांवों को मोबाइल सेवाओं से कवर नहीं किया जा सका है। कवर न किए गए गांवों में चरणबद्ध आधार पर मोबाइल सेवाएं उपलब्ध कराई जा रहीं हैं जिसमें भारतनेट परियोजना के अंतर्गत ग्राम पंचायतों को कनेक्टिविटी प्रदान करना और वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित क्षेत्र चरण-।। परियोजना के अंतर्गत कवरेज प्रदान करना शामिल है।

****